पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 22, अंक 3/2021

कोरोना महामारी के चलते सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में आई कठिनाई

विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पूर्व में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) निर्धारित किए गए थे, जो पूरी तरह से विकासशील देशों पर लागू होते थे। लेकिन इसके ठीक विपरीत सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) सभी देशों पर लागू होते हैं। एसडीजी के कार्यान्वयन में भारत की साढ़े पांच साल की प्रगति के मूल्यांकन से पता चलता है कि भारत को सतत् उपभोग और उत्पादन (एसडीजी 12) के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभावी निगरानी और डाटा संग्रह ढांचे की जरूरत है।

'कट्स' इंटरनेशनल, 'अनमोल फाउंडेशन' एवं छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के संयुक्त तत्वावधान में 30 सितम्बर 2021 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में यह उभरकर सामने आया।

कार्यशाला में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में 'कट्स' द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के हानिकारक प्रभाव और अन्य कारकों के कारण 2015 की तुलना में 2030 तक सतत् विकास के कई संकेतकों की स्थिति और खराब हो सकती है।

'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कार्यशाला के प्रारंभ में इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एसडीजी कार्यान्वयन में राज्य स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण बाधाएं सरकारी अधिकारियों के बीच जानकारी की कमी के साथ-साथ धन और तकनीकी कर्मचारियों की कमी के रूप में दिखाई देती है। जिसके परिणाम स्वरूप खराब निगरानी और रिपोर्टिंग होती है। उन्होंने कहा कि अगर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो यह टिकाउ खपत और उत्पादन के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों और प्रयासों पर एक नकारात्मक तस्वीर दिखा सकता है।

'कट्स' का एसडीजी 12 के संबंध में किया गया शोध 'सतत् उपभोग और उत्पादन-एक उपभोक्ता परिप्रेक्ष्य' उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से एसडीजी 12 पर ध्यान केंद्रित करता है और एक गाइड के रूप में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देशों का उपयोग करता है।

उन्होंने कहा कि लगभग सभी लक्ष्य एसडीजी 12 से जुड़े हुए हैं, जिसका अर्थ है कि एजेंडा 2030 की ओर देश की प्रगति एसडीजी 12 द्वारा उठाई गई समस्याओं को ठीक से संबोधित और हल किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजर्वेशन के साथ साझेदारी में एसडीजी 12 शीर्षक 'सतत् उपभोग और उत्पादन-एक उपभोक्ता परिप्रेक्ष्य' पर अध्ययन, मुख्य रूप से उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश के आधार पर एसडीजी 12 को एक उपभोक्ता दृष्टिकोण से देखा गया।

कार्यशाला में डॉ. के. सुब्रमण्यम, सदस्य, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि टिकाउ या जिम्मेदार उपभोग व्यवहार में दुनिया को बदलने की क्षमता है। टिकाउ उपभोग की आदतों और प्रवृत्तियों को बढ़ावा देकर, सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर अनूप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ ने एसडीजी पर सरकार की विभिन्न योजनाओं और की गई पहल पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला के दौरान अमरदीप सिंह, सीनियर प्रोग्राम ऑफीसर ने 'कट्स' द्वारा संचालित एसडीजी 12 से संबंधित विशिष्ट प्रगति और कार्यक्रमों की जानकारी को साझा किया गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विभिन्न क्षेत्रों और विभागों की सर्वोत्तम प्रथाओं और की गई पहल का दस्तावेजीकरण करके सतत् उपभोग और उत्पादन पर अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। कार्यक्रम में 12 शासकीय विभागों के साथ-साथ कई जिलों से स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

इस अंक में...

- अफसरों की लेटलतीफी में फंसे गरीबों के घर 3
- घूस के बिना कोई काम नहीं होता 5
- प्राकृतिक संसाधनों का करना होगा संरक्षण ... 6
- सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले पायदान पर 8
- देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भरोसे? 10

राजस्थान में जैविक उत्पादन और उपभोग का बढ़ता चलन-एक सुखद संकेत

वर्ष 2017 में एक बेसलाइन सर्वेक्षण में जहां 86 फीसदी उपभोक्ता इस बात से जागरूक थे कि रासायनिक तरीके से उगाए गए उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्हीं उपभोक्ताओं से वर्ष 2021 में प्राप्त एंडलाईन सर्वेक्षण में यह जानकारी बढ़कर 97.4 फीसदी हो गई है। इसी तरह वर्ष 2017 में जहां 19 फीसदी किसान ही जैविक खेती कर थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई है। यह भविष्य के लिए एक सुखद संकेत है।

यह सर्वेक्षण उपभोक्ता संस्था 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा प्रदेश के दस जिलों में संचालित प्रो-ऑर्गेनिक परियोजना के तहत करवाया गया। इसमें यह जानने का प्रयास किया गया कि जैविक खेती और जैविक पदार्थों के उपभोग के प्रति किसानों व उपभोक्ताओं में कितना रुझान बढ़ा है। एक रोचक प्रश्न के जवाब में सामने आया कि 66.8 फीसदी उपभोक्ता वर्तमान में जैविक उत्पाद खरीदने लगे हैं, जबकि वर्ष 2017 के दौरान यह केवल मात्र 39 फीसदी ही था। अर्थात लोगों में जैविक उत्पादों के प्रति तेजी से रुझान बढ़ा है।

राजस्थान में किसान कर रहे हैं खेती

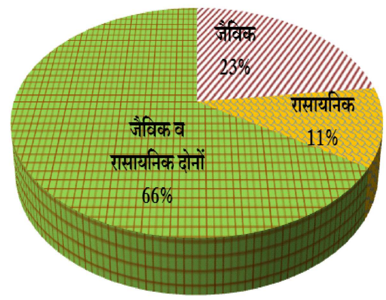

इसी तरह सर्वे में यह भी तथ्य सामने आया कि 23 फीसदी किसान पूर्ण रूप से जैविक खेती कर रहे हैं, वहीं 11 फीसदी किसानों ने बताया कि वे रासायनिक खेती कर रहे हैं, जबकि 66 फीसदी किसानों का कहना है कि वे रासायनिक और जैविक दोनों ही तरीकों से खेती कर रहे हैं।

दूसरी तरफ 2017 में 19 फीसदी पूर्ण रूप से जैविक, 26 फीसदी रासायनिक तथा 35 फीसदी किसान रासायनिक और जैविक दोनों तरीकों से खेती कर रहे थे। सर्वेक्षण के दौरान गुणात्मक विश्लेषण के तहत 2390 नमूनों के साथ एंडलाइन सर्वेक्षण में परियोजना से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों एवं कृषि विशेषज्ञों का मत है कि जैविक खेती को बढ़ाने के लिए राज्य में जैविक खेती आयोग या निगम बनाये जाने की आवश्यकता है। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार को वे सभी प्रयास करने चाहिए, जिससे जैविक खेती को तेजी से प्रोत्साहन मिल सके।

राज्य में सड़क सुरक्षा प्राधिकरण आवश्यक

घायलों की जान बचाना हमारा सभी का दायित्व: खाचरियावास

मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी 'कट्स' की ओर से जयपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने उद्बोधन में बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 2019 राज्य में भी लागू हो चुका है। इसके तहत सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना नहीं करने पर कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा हमें सड़क दुर्घटनाओं के कारणों पर ध्यान देना होगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाना भी हमारा सभी का दायित्व है। ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण होती है। उन्होंने ट्रोमा केयर पॉलिसी व बाल सुरक्षा पॉलिसी बनाने की आवश्यकता जताई। परिवहन मंत्री सहित सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी राज्य में सड़क सुरक्षा प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता जताई।

कार्यशाला के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने बताया कि 100 साल पहले बने अधिनियम में समय के अनुसार बदलाव की जरूरत थी। इस अधिनियम में संशोधन के लिए 'कट्स' लम्बे समय से कार्यरत रहा है। लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों से लगातार सम्पर्क करते हुए अधिनियम में संशोधन के लिए भारत सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव भी भिजवाए गए। संशोधित अधिनियम अब पूरे देश में लागू हो चुका है।

कार्यशाला में ए.डी.जी., ट्रैफिक पुलिस सुष्मित बिश्वास ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए रोड डिजाइनिंग की भी प्रमुख भूमिका होती है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि यातायात नियमों की जागरूकता के लिए राज्य के सभी 33 जिलों में ट्रेफिक पार्क बनाए जा रहे हैं।

सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के डॉ. गिरधर गोयल ने बताया कि घायल को तुरंत चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए अस्पताल में अलग से ट्रोमा केअर सेंटर है, जहां आधुनिक चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस अवसर पर संयुक्त परिवहन आयुक्त निधि सिंह एवं पीपुल्स ट्रस्ट की प्रेरणा सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने भी सड़क सुरक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए।

अफसरों की लेटलतीफी में फंसे गरीबों के घर

केंद्र या राज्य सरकार गरीबों के आवास के लिए योजनाएं तो खूब बनाती है, लेकिन क्रियान्विति में अफसरशाही की कछुआ चाल के चलते उनका लाभ गरीबों के लिए मात्र एक सपना बन कर रह जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में प्रदेश के करीब डेढ़ लाख गरीबों के घर का सपना लेटलतीफी में फंसा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 तक बीते करीब छह वर्षों में मंजूर हुए 1.43 लाख आवास आज भी अधूरे पड़े हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने फिसड्डी जिलों को नोटिस भी जारी किए जो अधरझूल में अटके हैं।

यही हाल राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री जन आवास के निर्माण का है, जहां जिम्मेदार अधिकारी सुध ही नहीं ले रहे। पिछले छह वर्षों में करीब 52 हजार आवासों की जेडीए ने विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति दी लेकिन अब तक सिर्फ 10 हजार लोगों को ही आवास मिले हैं। *(रा.प., 06.09.21)*

मनरेगा में 935 करोड़ रुपए की गड़बड़ी

पिछले चार साल के दौरान मनरेगा में 935 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी हुई है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों (एसएयू) के ऑडिट में यह गड़बड़ियां मिली हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रबंधन सूचना प्रणाली से 2017-18 से 2020-21 तक के यह आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। ऑडिट में पाया गया कि रिश्वत, फर्जी लोगों का नामांकन और सामान के लिए फर्जी विक्रेताओं को ऊंचे दामों पर भुगतान किया गया।

आंकड़ों के मुताबिक अभी तक केवल 12.5 करोड़ रुपए की ही भरपाई हो पाई है। तमिलनाडु में सबसे अधिक 245 करोड़ रुपए की वित्तीय हेराफेरी पाई गई है। राजस्थान, केरल, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, लक्ष्यद्वीप, पांडुचेरी, दादरा नागरा हवेली व दमन और दीव में कोई गड़बड़ी नहीं होने का दावा किया गया है। *(रा.प., 23.08.21)*

ई-मित्र प्लस मशीनें लगा कर भूली सरकार

प्रदेश में डिजिटल सेवाओं को सुगम बनाने के लिए 3 साल पहले शुरू किया ई-मित्र प्लस प्रोजेक्ट नकारा होता दिख रहा है। सरकार ने करीब 3.72 अरब रुपए खर्च कर 33 जिलों में 14 हजार 891 ई-मित्र प्लस मशीनें तो लगा दी, लेकिन इसके बाद इनकी सुध ही नहीं ली गई। इसलिए रोजाना एक चौथाई मशीनें भी नहीं चल रही है।

पिछली बार भाजपा सरकार के शासनकाल में लगाई गई इन मशीनों को लेकर सरकारी सिस्टम की लापरवाही का नतीजा यह रहा कि सरकारी कार्यालयों और बस स्टैंड पर रखी मशीनों पर धूल जम रही है। इसी कारण लोगों को जमाबंदी की नकल, मूल निवास प्रमाण-पत्र, बिजली पानी के बिल, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, राशनकार्ड आदि सेवाओं के लिए इन मशीनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। *(दै.भा., 29.09.21)*

अपात्र लोगों ने उठाई किसान सम्मान निधि

राजस्थान में अब तक 2 लाख 18 हजार 934 ऐसे लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल साधारण किसानों को दिए जाने वाले 6000 रुपए उठाते रहे, जो इसके लिए पात्र नहीं थे। इनमें कई हर महीने लाखों रुपए कमाने वाले, आयकर देने वाले और पेंशन धारक हैं। यहां तक कि कई लोगों के हाईवे पर कोठी और फार्म हाउस तक हैं।

लोकसभा में लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देते हुए बताया कि योजना के तहत पात्र किसानों के चयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लाभार्थियों के ब्यौरे का आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करने पर यह गड़बड़ी सामने आई। *(दै.भा., 04.08.21)*

डकार रहे राशनः गरीब का पीपा खाली

प्रदेश के सीकर जिले में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों की मौत के बाद भी राशन वितरण दिखाया जा रहा है। कई ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें सालों से राशन नहीं मिला, लेकिन उन्हें राशन देना दिखाया गया है। लोगों का आरोप है कि विभाग की शह से ऐसे घपले हो रहे हैं।

जिले के गोठड़ा तगेलान इलाके के लोगों ने ऐसे मामलों की साक्ष्यों के साथ रसद विभाग को शिकायत दी है। इसके बाद भी विभाग जांच के नाम पर खानापूर्ति करने में जुटा है। ग्रामीणों का कहना है कि सब कुछ ऑनलाइन होने पर भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। *(रा.प., 28.08.21)*

करोड़ों रुपए जमा पर काम एक भी नहीं

प्रदेश में खनन गतिविधियों से जिलों में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं। लेकिन इस पैसे के खर्चे को लेकर पक्ष-विपक्ष के बीच चल रही राजनीति होने से इसका लाभ जनता को समय पर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में दो वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में जमा हुए करीब 2100 करोड़ रुपए बैंकों में पड़े हैं, जिनका छह जिलों में अब तक एक काम भी स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

करीब दर्जनभर ऐसे जिले भी हैं, जिनमें पहले साल कोई काम नहीं हुआ और दूसरे साल भी गिनती के ही काम स्वीकृत हो पाए हैं। तीन जिले राजसमंद, अजमेर और चित्तौड़गढ़ ऐसे जिले रहे जहां बड़ी संख्या में काम स्वीकृत हो सके हैं। प्रदेश के जयपुर, अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर, करौली और सवाई माधोपुर तो ऐसे जिले हैं जहां एक भी काम स्वीकृत नहीं हुआ। *(रा.प., 29.09.21)*

बैंकों में जितनी पूंजी डाली, दोगुनी डूबी

देश के सरकारी बैंकों ने मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक करीब 8 लाख करोड़ रुपए के लोन को राइटऑफ किया है। यह राशि केंद्र सरकार की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में डाली गई कुल पूंजी से दोगुनी है। सरकार ने वर्ष 2014-15 से अब तक सरकारी बैंकों में 3,37,490 करोड़ रुपए की पूंजी डाली है, ताकि बैंक अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें।

इन 7 वर्षों में बैंकों ने 8,07,488 करोड़ रुपए के ऋण बट्टे खाते में डाले हैं। सरकार ने बैंकों में वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक 1.06 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाली थी और इसी वित्तीय वर्ष में बैंकों ने सर्वाधिक 1.83 लाख करोड़ के ऋण बट्टे खाते में डाले। बैंक अपनी बैलेंसशीट दुरुस्त करने के लिए भी डूबे हुए कर्ज को राइट-ऑफ कर देते हैं ताकि वे सरकार से अधिक फंड हासिल कर सकें। *(रा.प., 22.07.21)*

कई बजट घोषणाएं नहीं हो पाती पूरी

प्रदेश में बजट के समय घोषणाओं की सुखद बौछार तो होती है, लेकिन अनेक घोषणाओं को अगला बजट पारित होने के बाद भी पूरी होने का इंतजार रहता है। यह भी सच है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च सहित आखिरी तीन महीनों में बजट घोषणाओं पर सर्वाधिक पैसा खर्च होता है, जिससे आमजन को समय पर योजनाओं का लाभ नहीं मिलता।

यह खुलासा विधानसभा में पेश नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन में किया गया है। इनमें राज्य वित्त, योजनाओं के अनुपालन व उच्च शिक्षा की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के 2766 करोड़ रुपए का दिसंबर 2020 तक उपयोग ही नहीं हो पाया। *(रा.प., 15.09.21)*

उपभोक्ता कोर्ट में क्यों हैं पद खाली ?

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग व राज्यों में उपभोक्ता अदालतों में खाली पड़े पदों को न भरने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश राय की पीठ ने केंद्र व राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा 'क्या खाली पदों को भरने के लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालना पड़ेगा । लोगों को उम्मीद रहती है कि उनकी शिकायतों का जल्द निवारण होगा। इस उम्मीद को मत डुबाइए । हम खाली पदों पर नियुक्तियां चाहते हैं। केंद्र व सभी राज्य उपभोक्ता अदालतों में खाली पड़े सभी पदों को आठ सप्ताह के भीतर भरें ।'

कोर्ट ने कहा, अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो केंद्र के अफसरों और राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब करेंगे। *(दै.भा., 12.08.21)*

ट्रकों से रोज चोरी हो रहा राशन का गेहूं

भीलवाड़ा में एफसीआई के वेयर हाउस से जिन ट्रकों में गेहूं राशन की दुकानों पर भेजा जाता है, वह गेहूं बीच में ही 8 से 10 रुपए किलो में बेच दिया जाता है। इसके बाद यह दलाल इस गेहूं को बाजार में 15 से 17 रुपए किलो में बेचते हैं। चोरी पता नहीं चले, इसके लिए ट्रक में पत्थर भरकर वजन बराबर बनाए रखते हैं।

यह चौंकाने वाला खुलासा दैनिक भास्कर के दो रिपोर्टरों द्वारा तीन दिन स्टिंग के बाद किया गया है। हमीरगढ़ क्षेत्र के ओज्याड़ा में बने भारतीय खाद्य निगम के वेयर हाउस से रोज 80 से 100 ट्रक गेहूं निकलता है।

ट्रक ड्राइवर हाइवे की होटलों पर या बीच में दलालों को बुलाकर गेहूं बेच देते हैं। यह घपला अधिकारियों, कर्मचारियों व ड्राइवर की मिलीभगत के चलते हो रहा है। अब मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। *(दै.भा., 17.09.21)*

नहीं मिला महिलाओं व बच्चों को पोषाहार

बच्चों को जन्म से पहले (गर्भवती महिला के जरिए) और जन्म के बाद 6 साल तक पोषणयुक्त आहार खिलाने के सरकार के दावे पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। राजस्थान सरकार ऐसे 35 से 37 लाख बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आहार तो दे रही है लेकिन उसमें निर्धारित पोषण नहीं मिल रहा है।

राज्य में अभी चावल व गेहूं घर तक पहुंचाया जा रहा है और राज्य सरकार इसे ही पोषाहार मान बैठी है। जबकि केंद्र सरकार का आदेश है कि पहुंचाए गए राशन में पोषणयुक्त आहार होना जरूरी है। इसमें दलिया, पोहा, खिचड़ी, उपमा, मुरमुरे व फल सहित अन्य उत्पाद भी हो सकते हैं, जिसमें जरूरत के मुताबिक विटामिन व मिनरल्स मिलाने चाहिए। *(रा.प., 03.08.21)*

फूड सेफ्टी मामले में राजस्थान अनसेफ

चिकित्सा विभाग की ओर से मिलावट रोकने के दावे फेल साबित हो रहे हैं। शिकायत पर कार्रवाई, रिपोर्ट, फूड टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर व सर्विसेज, मेन पावर, प्रशिक्षण, जागरूकता और कंज्यूमर एंपावरमेंट के मामले में 100 में से मात्र 38 अंक मिले हैं। पैरामीटर पर खराब स्थिति रहने के कारण राजस्थान 18वें नम्बर पर है। ये ही नहीं पिछले साल की तुलना में 16 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है।

बड़े राज्यों के हिसाब से पहले नम्बर पर गुजरात, दूसरे पर केरल और तीसरे नम्बर पर महाराष्ट्र रहा है। यह खुलासा केंद्र के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथोरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की ओर से जारी 'फूड सेफ्टी इंडेक्स' की रिपोर्ट में हुआ है। *(दै.भा., 29.09.21)*

अपराधियों को नहीं रोक पा रही विधायिका

सुप्रीमकोर्ट ने राजनीति में अपराध पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि 'मालूम होता है कि अपराधियों को राजनीति में आने और चुनाव लड़ने से रोकने के लिए विधायिका कुछ नहीं कर सकती।' दागियों पर सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई पर जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की बेंच ने यह कहा । यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के खिलाफ दर्ज की गई थी ।

आदेश में कहा गया था कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों पर लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी अखबारों में विज्ञापन के जरिए सार्वजनिक करें। खेदजनक यह है, लोकसभा के हाल यह है कि 539 सांसदों में से 233 पर आपराधिक केस दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, दागी जनप्रतिनिधियों के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियमित तौर पर सुने जाने चाहिए । *(दै.भा., 21.07.21)*

सरकारी कर्मचारी खा गए गरीबों का गेहूं

प्रदेश में अच्छी तनख्वाह होने के बावजूद 85 हजार सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले दो रुपए किलो का गेहूं उठाकर खाते रहे। मामला खुला तो सरकार अब इनसे बाजार में बिक रहे आटे के भाव यानी 27 रुपए किलो के हिसाब से पैसा वसूल कर रही है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव नवीन जैन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 81 हजार 846 कर्मचारियों को रसद विभाग ने नोटिस दिए हैं। इनमें से 48 हजार 723 कर्मचारियों से 64 करोड़ 79 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है। अभी 33 हजार 123 से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली होना बाकी है। *(दै.भा., 28.07.21)*

एक साल में बढ़ गए भ्रष्टाचारी

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस वर्ष जुलाई में 51 भ्रष्टाचार के प्रकरण दर्ज किए हैं। जबकि इनमें गिरफ्तारी करीब 100 भ्रष्टाचारियों की हुई है। इनसे करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं। डीजी बीएल सोनी ने बताया कि वर्ष 2020 जुलाई में भ्रष्टाचार के प्रकरण दर्ज होने का आंकड़ा 43 था, जो इस वर्ष बढ़कर 51 हो गया।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष एसीबी ने बड़ी संख्या में प्रकरणों का निस्तारण करने का भी निर्णय लिया है। दर्ज आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष 388 प्रकरणों में मुख्यालय स्तर पर अनुसंधान पूर्ण होने पर निर्णय लिया गया। गत वर्ष इस अवधि में 118 प्रकरणों में निर्णय हुआ था। डीजी बीएल सोनी ने कहा कि घूस देने के बजाय लोग भ्रष्टाचार की शिकायत टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर करें। *(रा.प. एवं दै.भा., 04.08.21)*

अघोषित संपत्ति का किया खुलासा

पनामा पेपर्स खुलासे के बाद से भारत में 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित संपत्ति का पता चला है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सूचना का अधिकार के एक आवेदन के जवाब में बताया कि उनके द्वारा जून 2021 तक पनामा पेपर्स से जुड़ी 20,078 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया गया है। सीबीडीटी ने पिछले महीने तक देश में विभिन्न अदालतों में काला धन अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत 46 मामले दायर किए हैं। वहीं 83 मामलों में तलाशी आदि की गई है। सीबीडीटी ने उन लोगों से 142 करोड़ रुपए का कर वसूल किया है।

पलित्जर विजेता खोज 'पनामा पेपर्स' के तहत भारत समेत दुनियाभर के धनकुबेरों की छिपाई संपत्ति का खुलासा किया गया है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की तरफ से 17 जून को जारी सालाना डेटा के मुताबिक साल 2020 के दौरान स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों, संस्थानों व कंपनियों का धन बढ़कर करीब 20,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। *(रा.प., 07.07.21)*

कौशल विकास में भ्रष्टाचार का कौशल

बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास करने के नाम पर राजस्थान राज्य कौशल विकास निगम (आरएसएलडीसी) के अफसर और कर्मचारी भ्रष्टाचार का अपना कौशल बढ़ाने में लगे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आरएसएलडीसी में चल रहे ऐसे ही बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए निगम के कॉर्डिनेटर अशोक सांगवान, मेनेजर राहुल गर्ग को 5 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों ने यह राशि डेढ़ करोड़ रुपए के बिल पास करने और फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं करने की एवज में ली थी। मामले में श्रम, रोजगार एवं स्किल विभाग के सचिव (आइएएस) नीरज के. पवन के अलावा कई अन्य अधिकारी भी फंसे हुए हैं। यदि राजस्थान कौशल विकास आजीविका निगम की पड़ताल करें तो कदम-कदम पर फर्जीवाड़े की तह खुल सकती है। पिछले सालों में प्रशिक्षणार्थियों के थंब क्लोनिंग कर हाजिरी के नाम पर करोड़ों रुपए उठाने के मामले सामने आए थे। लेकिन अफसर गए, मामले दब गए। *(दै.भा. एवं रा.प., 12.09.21 एवं 13.09.21)*

घूस के बिना कोई काम नहीं होता

व्यक्ति के जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं। इन संस्कारों को पूरा करने मे भी सरकारी कर्मचारियों को घूस देनी पड़ती है। आलम यह है कि जन्म से मृत्यु तक के कामों के लिए लोगों को घूस देनी पड़ी। मसलन, लोगों को विवाह संस्कार के प्रमाण-पत्र के लिए 600 रुपए और मृत्यु बीमा क्लेम के लिए एक लाख रुपए तक की घूस देनी पड़ी है।

घूसखोरी के मामले में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी शीर्ष पर है। शिक्षा से जुड़े कामों के लिए लोगों को कुल 45 लाख 7 हजार 500 रुपए की घूस देनी पड़ी। यह जानकारी तब सामने आई जब भास्कर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की इस साल जनवरी से जुलाई तक घूसखोरों पर की गई कार्रवाई की पड़ताल की। एसीबी ने इस दौरान 262 ट्रेप की कार्रवाई की, जिनमें कुल 309 अफसर -कर्मचारी घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए। इन लोगों ने 133 अलग-अलग कामों के बदले कुल एक करोड़ 28 लाख 92 हजार रुपए की घूस ली। *(दै.भा., 02.09.21)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
जयपुर	सज्जन सिंह गुर्जर	कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान लोक सेवा आयोग	23,00,000	*रा.प. एवं दै.भा., 10.07.21*
चूरू	मो.आरिफ कायमखानी	अनुबंधित वाहन चालक, श्रम विभाग कार्यालय	1,00,000	*रा.प., 13.07.21*
अलवर	रमेश सिंह	सहायक अधिशाषी अभियंता, उत्तर-मध्य रेलवे	1,50,000	*रा.प., 19.07.21*
बाड़मेर	सोहन लाल सुथार	एइएन, धोरीमन्ना पंचायत समिति, बाड़मेर	5,00,000	*दै.भा. एवं रा.प., 29.07.21*
जोधपुर	सीमा रामावत	पटवारी, केरू, जोधपुर	1,00,000	*दै.भा. एवं रा.प., 06.08.21*
जयपुर	अमृत लाल मीणा	प्रोजेक्ट मैनेजर, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट निर्माण निगम	1,00,000	*दै.भा. एवं रा.प., 04.09.21*
जयपुर	अशोक संगवान राहुल कुमार गर्ग	को-ऑर्डिनेटर, राजस्थान राज्य कौशल विकास निगम प्रबंधक, राजस्थान राज्य कौशल विकास निगम	5,00,000	*दै.भा. एवं रा.प., 12.09.21*

प्राकृतिक संसाधनों का करना होगा संरक्षण

'हमें सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। इसके लिए समाज में शेयरिंग कम्यूनिटी की भावना से काम करने के लिए सभी को जागृत करना जरूरी है।'

उक्त विचार 'कट्स' के निदेशक जार्ज चेरियन ने 9 सितम्बर, 2021 को जयपुर में आयोजित 'ग्रीन एक्शन वीक' अभियान की शुरुआती बैठक में व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि 'ग्रीन एक्शन वीक' प्रति वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जो सतत् उपभोग को बढ़ावा देता है। यह अभियान स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन के सहयोग से वैश्विक स्तर पर आयोजित किया जाता है। इस अभियान में 50 देशों की करीब 50 संस्थाएं भाग लेती है। 'कट्स' द्वारा भारत में यह अभियान संचालित किया जा रहा है।

कार्यशाला के दौरान कार्यक्रम प्रभारी निमिषा शर्मा ने बताया कि 'ग्रीन एक्शन वीक' 2021 अभियान का इस वर्ष का विषय 'शेयरिंग कम्यूनिटी' है। यह अभियान समुदाय के सामूहिक साझेदारी और सहयोग की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित है। साथ ही सतत् उपभोग को भी बढ़ाया जा रहा है। कार्यशाला में 'कट्स' के राजदीप पारीक ने बताया कि किचन गार्डनिंग, घर के कचरे से कम्पोस्ट बनाना, ई-वेस्ट का सही निस्तारण करना, कबाड़ से जुगाड़ बनाना आदि कई ऐसी गतिविधियां हैं, जिनसे हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर चयनित 25 महिलाओं को किचन गार्डन के लिए सब्जियों के बीज भी वितरित किए गए।

गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वह खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एंबेसडर होंगे और इसे पूरे देश में बढ़ावा देंगे। उन्होंने जयपुर में खादी प्राकृतिक पेंट की पहली स्वचालित निर्माण इकाई का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कहा कि यह किसानों की आय बढ़ाने और स्वरोजगार पैदा करने के लिए शुरू की गई है।

गाय के गोबर से बनाया गया यह पेंट डिस्टेंपर और इमल्शन में मिलेगा। यह पेंट पर्यावरण अनुकूल, गंधहीन और सस्ता होगा। उन्होंने कहा वह इसे पूरे देश में बढ़ावा देंगे ताकि युवा उद्यमियों को पेंट का निर्माण करने को प्रोत्साहित किया जा सके। हमारा लक्ष्य हर गांव में एक प्राकृतिक पेंट इकाई स्थापित करने का होना चाहिए। *(रा.प., 07.07.21)*

मौसम बदलाव पर यूएन की रिपोर्ट

आने वाले सालों में भारत समेत पूरे एशिया में तापमान सबसे तेजी से बढ़ेगा। गर्म हवाएं और चक्रवर्ती तूफान पहले के कई वर्षों की तुलना में ज्यादा आएंगे। समुद्री तटों व पहाड़ों पर जनजीवन और मुश्किल होगा। बादल फटने, सूखा, अधिक गर्मी और चक्रवाती तूफान में आगामी वर्षों में तेजी से बढ़ोतरी होगी। 20 वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाएगा। इसका दुष्प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति, जीवों और पेड़-पौधों की सेहत और जीवनकाल पर पड़ेगा।

यह खुलासा संयुक्त राष्ट्र संघ के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आइपीसीसी) वर्किंग ग्रुप वन की रिपोर्ट 'क्लाइमेट चेंज 2021ः द फिजीकल साइंस बेसिस' में हुआ है। इसमें क्लाइमेट चेंज पर 14 हजार से अधिक शोध पत्रों पर 234 वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। *(रा.प., 10.08.21)*

महामारी से निपटने के लिए बड़ी घोषणा

केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में सेहत के लिए बड़ा फैसला किया गया है। इसके तहत भविष्य में महामारी से निपटने के लिए 23 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि इसका उपयोग केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से करेंगी। इसमें 15 हजार करोड़ रुपए की भागीदारी केंन्द्र की होगी और 8 हजार करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी।

मंडाविया ने बताया कि 736 जिलों में बाल चिकित्सा देखभाल केंद्र बनाए जाएंगे एवं कोरोना राहत कोष के तहत 20,000 आइसीयू बेड बनाए जाएंगे। हर जिले में एक करोड़ की दवा का बफर स्टॉक होगा एवं हर जिले में 10 हजार लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। *(रा.प., 09.07.21)*

देश में अगले साल से प्लास्टिक बंद

केंद्र सरकार ने अगले साल तक देश को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से मुक्त करने की दिशा में कदम उठाया है। कप-प्लेट सहित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गजट नोटिफिकेशन (राजपत्र अधिसूचना) जारी किया गया है।

इसके मुताबिक एक जुलाई 2022 से पॉलिस्टाइनिन और एक्सपेंडेड पॉलिस्टाइनिन सहित सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित होगा। इसका निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग जैसी हर तरह की गतिविधि पर प्रतिबंध होगा। कूड़ा-कचरा कम करने के लिए 30 सितंबर 2021 से हल्के वजन वाली प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन होगी। 31 दिसम्बर 2022 से केवल 120 माइक्रोन की मोटाई के कैरी बैग इस्तेमाल हो सकेंगे। *(रा.प.एवं दै.भा., 14.08.21)*

अच्छे सुझावों से सरकारी कामकाज होगा बेहतरः राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के अच्छे सुझावों से सरकारी कामकाज और बेहतर हो सकता है। लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली की गहरी समझ सरकार के लिए मददगार हो सकती है।

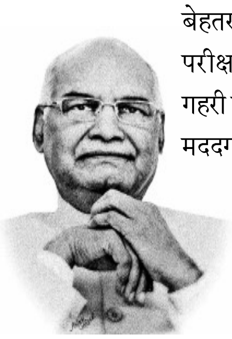

राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी (यारोज) में वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए यह कहा।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारी अगर आगे चलकर गरीब लोगों की सेवा करेंगे, तो इससे अधिक संतुष्टि होगी। सभी युवा अधिकारी प्रशिक्षण के समय मिली सीख का अनुसरण करते हैं, तो इससे देश को लाभ होगा। संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए सभी अधिकारियों की मेहनत से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। बेहतर काम काज से राज्य सरकारें भी सीएजी जैसी संस्था को गंभीरता से लेगी। *(दै.भा., 19.09.21)*

ओबीसी आरक्षण को मिली मंजूरी

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार देने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा में बहुमत से मंजूर हुए इस विधेयक पर राज्यसभा में भी किसी ने विरोध नहीं किया। विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है।

विधेयक के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक समय है। यह सरकार की वंचित वर्गों की गरिमा, अवसर और न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह विधेयक सामाजिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएगा। कानून बनने के बाद राज्य अपने हिसाब से ओबीसी सूची तैयार कर सकेंगे। पहले यह सूची बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास था।

ग्रामीण युवाओं को मिले कौशल प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भविष्य में ग्रामीण स्तर पर युवाओं की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। गांवों में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर की मांग बढ़ेगी। ऐसे में, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से अधिक से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर जैसे कोर्स में प्रशिक्षित किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रेनिंग देने वाली फर्म से किए समझौते की शर्तों के मुताबिक निर्धारित संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएं, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्किल डवलपमेंट के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य तय कर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित किया जाए। *(रा.प. 06.07.21)*

अब 'डिजिटली आयुष्मान' होगा भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' की शुरुआत करते हुए बताया है कि इसके तहत देश के हर नागरिक का यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनेगा। 14 डिजिट वाले इस कार्ड को आपके ईमेल आईडी से भी जोड़ा जाएगा, ताकि आप जब चाहें अपना पिछला हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल पर भी देख सकें। इस कार्ड से लोगों को मेडिकल रिकॉर्ड की फाइलें साथ रखने से छुटकारा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए क्रांतिकारी बदलाव आएगा। अब इलाज के लिए अस्पताल में बीमारी संबंधी पुराने पर्चे और जांच रिपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर यूनिट हेल्थ कार्ड के आधार पर इलाज की दिशा तय कर सकेंगे। इस योजना को अभी छह केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। *(दै.भा. एवं रा.प., 28.09.21)*

कोरोना से मौत पर मिलेगा मुआवजा

कोरोना (कोविड-19) से मृत्यु पर मृतक के परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी है। हलफनामे में कहा गया है कि मुआवजे का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। यह अनुग्रह राशि महामारी के भविष्य के चरणों में भी या अगली अधिसूचना तक दी जाती रहेगी।

उन मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा, जो कोविड राहत कार्यों में शामिल थे या तैयारी की गतिविधियों से जुड़े थे। मुआवजा देने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जारी निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। दावों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा। शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर समिति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के कारण जिन लोगों की मौत घरों में हुई है, उनके परिजन भी मुआवजे के हकदार होंगे। *(रा.प., 23.09.21)*

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ें

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि डोर-टू-डोर सर्वे किया जाकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के तहत सभी पात्र परिवारों को जोड़ा जाना सुनिश्चित करें। यह योजना जनता को उपचार के महंगे खर्च से बचाएगी। इसमें राजकीय अस्पतालों के साथ-साथ लोगों को निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज कराने की सुविधा है।

उन्होंने कहा कि एक भी जरूरतमंद पात्र परिवार इस योजना में रजिस्ट्रेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अस्पतालों में इस योजना का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं आए। इसके लिए अस्पतालों में हैल्प डेस्क बनें। *(रा.प., 12.08.21)*

मनरेगा रोजगार में फिर बनेगा रेकॉर्ड

कोरोना काल में पिछले साल प्रदेश में एक करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका देकर रोजगार का सबसे बड़ा जरिया बनी मनरेगा फिर से नया रेकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। राज्य में मनरेगा ने पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार देकर एक रेकॉर्ड बनाया था।

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक उम्मीद की जा रही है कि मनरेगा रोजगार के मामले में पिछले रेकॉर्ड को तोड़ देगा। कोरोना की दूसरी लहर में चालू साल में मजदूरों की संख्या बढ़ती दिख रही है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों से लौटकर आ रहे हैं, उन्हें मनरेगा में काम मिल सकेगा। *(रा.प., 05.07.21)*

सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अक्षय ऊर्जा के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2019 और सोलर-विंड हाईब्रिड ऊर्जा नीति-2019 लागू की है। इससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और मेगा सोलर पार्क परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा मिला है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की बैठक को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं को कस्टमाइज पैकेज स्वीकृत करने से राज्य में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। वर्ष 2024-25 तक तय 30 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा एवं 7500 मेगावाट विंड तथा हाईब्रिड एनर्जी उत्पादन के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले पूरा करने का प्रयास करें। *(दै.भा., 03.07.21)*

महंगी बिजली : विधानसभा में उठा सवाल

बिजली उत्पादन में कोयले की कमी, महंगी बिजली खरीद, उपभोक्ता की निराशा जैसे कई मुद्दों पर विधानसभा में विपक्ष (बीजेपी) ने स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बिलों में हो रही बेतहाशा वृद्धि पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी उपभोक्ता ऐसा नहीं बचा जिसे बिजली ने करंट नहीं मारा हो।

राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार ने कई बार कहा कि प्रदेश बिजली की दृष्टि से आज आत्मनिर्भर है, फिर बिजली कटौती क्यों हो रही है? महंगी बिजली खरीदी जा रही है, जिसमें गड़बड़ी के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि सरकार बिजली सरप्लस होने और दरें नहीं बढ़ाने की बात करती रही है लेकिन चोर दरवाजे से बिजली की दरें बढ़ा कर आम उपभोक्ता और किसानों के साथ धोखा कर रही है। *(दै.भा., 14.09.21)*

विकसित होगा सोलर पार्क

राज्य में सालाना 340 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन का नया सोलर पार्क विकसित होगा। राज्य सरकार ने विद्युत उत्पादन निगम को 2 हजार मेगावॉट क्षमता के सोलर पार्क के लिए स्वीकृति दे दी है। प्रदेश में पहली बार सरकारी उपक्रम सोलर पार्क विकसित करेगा।

इसके जरिए 2.15 से 2.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध होने का अनुमान है, जबकि थर्मल प्लांट से औसतन बिजली उत्पादन की लागत 4.30 रुपए प्रति यूनिट आ रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए 6500 हैक्टेयर जमीन जैसलमेर में चिन्हित कर ली गई है। इसी सोलर पार्क में पहले फेज में उत्पादन निगम खुद का 810 मेगावॉट का प्लांट लगाएगा। वहीं दूसरा फेस 1190 मेगावॉट क्षमता का प्लांट निगम स्तर पर ही लगेगा या फिर निजी डवलपर लगाएगा। यह सरकार के स्तर पर तय होना है।

(रा.प., 12.08.21)

मीटरों में गड़बड़ी, जनता की जेब ढीली

जयपुर डिस्कॉम की ओर से लगाए गए सिंगल फेज के कई मीटर न केवल तेज चल रहे हैं, बल्कि विद्युत सप्लाई बंद करने के बाद भी उनमें लगातार रीडिंग अंकित हो रही है। इसकी वजह से जनता की जेब ढीली हो रही है। उपभोक्ताओं की शिकायत और विभागीय जांच के बाद अब तक ऐसे 10 हजार से ज्यादा गड़बड़ी वाले मीटर पकड़े जा चुके हैं।

इससे घबराए हुए इंजीनियर अब अनुबंधित कंपनी जीनस से ऐसे मीटरों को बदलवा रहे हैं। गौरतलब यह है कि कंपनी को सप्लाई किए गए मीटरों के बदले पहले ही भुगतान किया जा चुका है, जबकि डिस्कॉम ने कंपनी के सभी तरह के भुगतान पर रोक लगाई थी। इससे अफसरों की कार्यशैली कटघरे में हैं। *(रा.प., 17.07.21)*

पानी में होगी बिजली स्टोरेज

अब सूरज और हवा से मिलने वाली बिजली का स्टोरेज किसी बैट्री में नहीं, बल्कि पानी में होगा और जरूरत पड़ने पर इस बिजली का उपयोग कर सकेंगे। राजस्थान में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। इंटीग्रेटेड पंप स्टोरेज के रूप में सूरज, हवा और ग्रिड तीनों जरिए से मिलने वाली बिजली को स्टोरेज करने वाला देश में यह पहला प्रोजेक्ट होगा। इसके लिए पाली और बारां में जमीन चिन्हित कर ली गई है।

राज्य सरकार ग्रीनको एनर्जी के इस हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए दोनों जगह जमीन लीज पर देगी। इसके जरिए एक समय में 2520 मेगावॉट बिजली का स्टोरेज किया जा सकेगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इस प्रक्रिया का अध्ययन कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की मियाद अधिकतम तीन साल है। *(रा.प., 14.08.21)*

सौर ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे हैं कदम

प्रदेश पिछले एक दशक में सौर ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। वर्ष 2011 में केवल 5 मेगावॉट सौर ऊर्जा बनती थी। और आज पूरे प्रदेश में 7 हजार मेगावॉट बिजली बनने लगी है। केंद्र से मिला 31 दिसम्बर 2022 तक 5762 मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य अभी ही पूरा हो चुका है।

देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर है। राज्य सरकार ने अब 2024-25 तक प्रदेश में 30 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 33 में से 20 जिलों में सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इसमें से सर्वाधिक 3837 मेगावॉट सौर ऊर्जा जोधपुर में पैदा हो रही है, जबकि 1200 मेगावॉट के साथ जैसलमेर दूसरे स्थान पर है। इसके बाद बीकानेर, भीलवाड़ा व पाली का स्थान है। *(रा.प., 20.08.21)*

सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले पायदान पर

सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान देश में पहले पायदान पर है। कर्नाटक को पछाड़ कर राजस्थान में 7738 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता हो गई है। कर्नाटक में 7469 और 5708 मेगावाट क्षमता के साथ गुजरात तीसरी पायदान पर है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय रिपोर्ट में इसकी पुष्टी हुई है।

सूरज से ज्यादा बिजली लेने के लिए प्रदेश में लगातार सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं और वर्ष 2030 तक 30 हजार मेगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित है। नई सोलर पॉलिसी में भी यह अंकित है। अक्षय ऊर्जा निगम के अफसरों का दावा है कि प्रदेश में जिस तरह काम हो रहा है, अब राजस्थान आगे भी अव्वल ही रहेगा। *(रा.प., 23.09.21)*

वर्षाजल सहेजना होगा अनिवार्य

प्रदेश में अब कम से कम 225 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड-भवन पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना जरूरी हो गया है। इतने व इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखंडधारियों को बारिश के पानी को सहेजना आवश्यक होगा। अभी 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों पर ही यह लागू था। जिनकी संख्या अभी केवल 4 से 5 लाख ही है। 225 वर्गमीटर भूखंड पर छत का अधिकतम निर्मित एरिया 2421 वर्गफीट होगा, जिससे दो साल से ज्यादा पानी जमीन में संचित कर पाएंगे। अभी यह पानी सीवर लाइन या नालों में बह रहा है।

इसके अलावा पानी को दोबारा उपयोगी बनाने के लिए अब 5 हजार की जगह 2500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर बनने वाले बहुमंजिला आवास व आवासीय योजनाओं में भी अब ट्रीटमेंट प्लांट बनाना जरूरी हो गया है। नगरीय विकास विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद मॉडल बिल्डिंग बाईलॉज में संशोधन कर दिया गया है।

(रा.प., 08.09.21)

परकोटे में सुधरेगी पेयजल की आपूर्ति

जलदाय विभाग जयपुर के परकोटा क्षेत्र में पेयजल सप्लाई के दौरान कम दबाव और कम समय तक पानी आने की समस्या के समाधान की कवायद में जुट गया है। इसके लिए परकोटा क्षेत्र में एक करोड़ तीस लाख लीटर पानी के स्टोरेज की योजना बना रहा है।

ब्रह्मपुरी में 50 लाख लीटर के स्वच्छ जलाशय निर्माण की योजना को अंतिम रूप देने के बाद मिस्त्रीखाना में 80 लाख लीटर की क्षमता का स्वच्छ जलाशय का निर्माण होगा। इससे ढाई लाख से ज्यादा आबादी के लिए निर्बाध पेयजल सप्लाई हो सकें। इस योजना के धरातल पर उतरने के बाद क्षेत्र में ज्यादा समय तक बीसलपुर सिस्टम से पेयजल सप्लाई होगी और पहले से ज्यादा पानी मिलेगा। *(रा.प., 04.07.21)*

प्रदेश में बढ़ा भूजल का दोहन

राज्य सरकार की ओर से बीते साल प्रदेश में पांच श्रेणियों में बोरिंग खोदने की अनुमति देने के बाद इस छूट का लाभ लेते हुए दनादन बोरिंग खुदने शुरू हो गए हैं। इस अवधि में कितने बोरिंग खुदे इसकी जानकारी किसी भी जिले के प्रशासन को नहीं है। लेकिन बेहिसाब बोरिंग खुदने से जमीन का सीना छलनी हो चुका है। *इस छूट की भयावह तस्वीर तीन साल बाद होने वाले भू-जल सर्वे से पहले ही नजर आने लगी है।

भूजल विभाग की ओर से हाल ही में दी गई भूजल स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 और 2017 में भूजल के दोहन की स्थिति के विपरीत 2020 में 10.34 प्रतिशत भूजल का दोहन बढ़ गया है। जितना पानी जमीन में जा रहा है उसके मुकाबले 150.22 प्रतिशत पानी को जमीन से खींचा जा रहा है। अगर भूजल दोहन इसी तरह होता रहा तो हालात विकट होंगे।

(रा.प., 12.08.21)

पानी की गुणवता की होगी जांच

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश के हर जिले और ब्लॉक में नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टि एंड केलिब्रेशन लेबोरेटरीज(एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का निर्माण होगा। अभी तक देश में ऐसी 2 हजार प्रयोगशालाएं तो बनकर तैयार भी हो चुकी है।

उन्होंने बताया कि जलशक्ति मंत्रालय एक ऐसा पोर्टल विकसित कर रहा है जिससे देश के किसी भी गांव, मोहल्ले व घर में कैसा पानी पहुंचा है इसकी पूरी जानकारी मिल सकेगी। इससे पहले कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि करीब छह लाख से भी ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को पानी की गुणवत्ता जांचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे हर गांव में प्रशिक्षित महिलाएं होंगी और उनके पास टेस्टिंग किट होंगे। वे कहीं भी जाकर पानी की जांच कर सकेंगी। *(दै.भा., 13.09.21)*

ग्रामीण घरों तक जल कनेक्शन

प्रदेश के 101.32 लाख ग्रामीण घरों में से केवल 21 लाख घरों में नल से जल की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2020-21 में करीब 6.77 लाख नए कनेक्शन लगाए गए हैं। अब वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने 30 लाख नए कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2020-21 में राजस्थान को केंद्र सरकार ने 2522 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब वर्ष 2021-22 में इसे बढ़ाकर 10180.50 करोड़ रुपए किया गया है।

यह जानकारी केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने देते हुए कहा कि 15 वें वित्त आयोग के तहत राजस्थान के पंचायतीराज संस्थाओं को 2021-22 में 1712 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें से 50 प्रतिशत राशि जलापूर्ति और स्वच्छता पर खर्च की जानी है।

(रा.प., 14.09.21)

हर घर तक नल से पहुंच रहा है पानी

प्रदेश में जलजीवन मिशन के तहत घर-घर सरकारी नल से पानी पहुंचाने का कार्य अब रफ्तार पकड़ रहा है। इस वित्तीय वर्ष में अप्रेल से लेकर 5 अगस्त तक प्रदेश के 618 गांवों और 63 पंचायतों के एक लाख 790 घरों में सरकारी नल से पानी पहुंचाने का काम पूरा हो गया है।

प्रदेश के 43 हजार 362 गांवों और ढाणियों में 20 लाख 59 हजार 435 परिवारों को सरकारी नल से पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2019 से लेकर अब तक 8 लाख 85 हजार 304 से अधिक परिवारों को पेयजल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इस साल मिशन के तहत 30 लाख घरों में सरकारी नल से पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। राज्य में कोरोना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों पर आर्थिक रूप से विपरीत प्रभाव पड़ा है। *(रा.प., 06.08.21, 25.09.21)*

अब शोधित जल से बढ़ेगी हरियाली

गुलाबी नगर के पार्कों में अब जेडीए ग्राउंड वाटर का नहीं बल्कि सीवरेज का शोधन करने के बाद जो पानी साफ होगा उसका उपयोग किया जाएगा। सेंट्रल पार्क, रामनिवास बाग, जवाहर सर्किल के अलावा वुडलैंड पार्क में पानी के स्टोरेज के टैंक भी बनवाए जाएंगे।

जेडीए की उद्यान शाखा ने टैंक निर्माण का प्रस्ताव बनाकर इंजीनियरिंग विंग को दे दिया है। इससे भूजल पर निर्भरता कम होगी और ग्राउंड वाटर का दोहन रुकेगा। करीब 95 फीसदी पार्कों में सिंचाई और पौधों में पानी देने में भूजल का ही उपयोग किया जा रहा है।

(रा.प., 27.09.21)

देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भरोसे?

कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न कामकाज पर गहरा असर पड़ा, लेकिन देश में कृषि क्षेत्र लगातार बेहतर बना रहा। बावजूद इसके खेतिहर मजदूरों को ज्यादा लाभ नहीं हुआ। इसमें रोजी-रोटी पा रहे मजदूरों खासकर महिलाओं के समक्ष बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है और उनकी आमदनी कम हुई है।

यह तथ्य इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट से सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, जिन राज्यों में पलायन ज्यादा हुआ है, वहां महिलाओं की स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है। महिला किसान अधिकार मंच की सीमा कुलकर्णी ने बताया कि शहरों से मजदूरों के गांव लौटने से उन परिवारों की आमदनी पर ज्यादा असर पड़ा है जो पूरी तरह खेती पर निर्भर हैं। गांवों में रहने वाली अकेली महिलाओं की स्थिति तो और भी बिगड़ी है।

(रा.प., 11.09.21)

फैमिली प्लानिंग महिलाओं के जिम्मे

चिकित्सा विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी पुरुष नसबन्दी से दूर हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम व योजनाओं के बाद भी महिलाओं की तुलना में पुरुष नसबन्दी के आंकड़े बेहद खराब है। फैमिली प्लानिंग का 99 फीसदी जिम्मा महिलाओं पर है और महज एक फीसदी पुरुषों पर।

पुरुष नसबन्दी में पिछड़ने का प्रमुख कारण कमजोरी आने, वैवाहिक जीवन प्रभावित होने जैसे मिथक और फैली भ्रांतियां हैं। जबकि एक्सपर्ट का दावा है कि इससे कोई परेशानी नहीं होती। इधर चिकित्सा विभाग ने वर्ष 2021-22 में परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत नसबन्दी का लक्ष्य 2 बच्चों पर ही निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अधिक बच्चों वाले दंपत्तियों को भी नसबन्दी की सेवाएं दी जाएगी।

(दै.भा., 12.07.21)

बाल विवाह के खिलाफ आई जागरूकता

राजस्थान में बाल विवाह ही नहीं बालिकाओं का कम उम्र यानी 14-15 साल की आयु में गौना होना भी बड़ी समस्या है। यहां हर 10 में से 4 लड़कियों का बाल विवाह हो रहा है। हालांकि सरकार, स्वयंसेवी सस्थाओं और यूनीसेफ के संयुक्त प्रयासों से धीरे-धीरे ही सही, बालिकाओं में जागरूकता आ रही है।

अनेक बालिकाएं अब बाल विवाह का प्रतिकार करने लगी हैं। इसके अलावा उनका अगर छोटी उम्र में बाल विवाह हो भी गया हो तो वे ऐसी शादी को निरस्त भी करवा रही हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी 579 साहसी बालिकाओं ने स्वयं अपना बाल विवाह रुकवाया।

इन्हें ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर सम्मान दिया गया। पिछले 5 साल में 2634 संभावित बाल विवाह के प्रकरण समझाइश से रोके गए। बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान से भी लोगों में जागृति आई है। इससे बालिकाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। *(दै.भा., 18.07.21)*

ऑनलाइन पढ़ाई : बच्चों की नींव कमजोर

कोरोना महामारी को चलते 18 महीने पूरे हो चुके हैं और स्कूली बच्चों सहित प्रोफेशनल कक्षाओं वाले बच्चों की ऑफलाइन कक्षाएं अभी भी बंद हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के विशेषज्ञों ने इसके दुष्परिणाम गिनाते हुए कहा है कि इसके नतीजे बच्चों और उनके अभिभावकों को आने वाले कई सालों तक भुगतने पड़ सकते हैं।

विशेषज्ञों ने माना है कि ऑनलाइन कक्षा में बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, साथ ही यह उन छोटे बच्चों के लिए सर्वाधिक घातक साबित हुआ है, जिनकी प्री प्राईमरी कक्षा कक्षाएं थी और वे स्कूल जाना सीख रहे थे। इसके अलावा प्रोफेशनल परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का कीमती समय भी ऑनलाइन पढ़ाई की भेंट चढ़ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस नुकसान की भरपाई की गाइडलाइन जरूरी है। *(रा.प., 06.08.21)*

ग्रामीण खेलों के लिए मोबाइल ऐप

राज्य के खेल मंत्री अशोक चांदना ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। संभवतया नवंबर में होने वाले ग्रामीण ओलंपिक के लिए गांव के युवा घर बैठे 'मोबाइल ऐप' के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह ऐप राजस्थान राज्य खेल परिषद् की साइट पर उपलब्ध है।

स्पोर्ट्स काउंसिल की वेबसाइट www.rssc.in पर भी यह ऐप उपलब्ध है। चांदना ने कहा कि इस तरह के खेल पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। इन खेलों में छोटे से छोटे गांव के पुरुष एवं महिला खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। इससे ग्रामीण प्रतिभाएं आगे आएंगी और वे अगले ओलम्पिक, पैरा ओलम्पिक खेलों में भाग ले सकेंगे। *(रा.प. एवं दै.भा., 08.09.21)*

श्रमबल में बढ़ी महिलाओं की भागीदारी

देश के श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हाल में जारी श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में 15 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की श्रमबल में भगीदारी दर 5.5 प्रतिशत बढ़कर 24.5 से 30 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

वित्त वर्ष 2019-20 में वित्त वर्ष 2018-19 के मुकाबले महिला श्रमिकों की संख्या 29 प्रतिशत बढ़ी। महिला श्रमिकों की संख्या में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई, जब देश में बेरोजगारी दर चरम पर थी और तेजी से बढ़ रही थी। वहीं देश की अर्थव्यवस्था भी कोरोना महामारी की चपेट में थी और ग्रोथ रेट में लगातार गिरावट आ रही थी।

श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने यह जानकारी देते हुए बताया कि श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। श्रम कानूनों में जहां सुरक्षात्मक प्रावधान किए हैं, वहीं अनेक सुविधाएं भी दी गई हैं और नए रोजगारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(रा.प., 29.07.21 एवं 05.08.21)

अच्छा मददगार विषय पर कार्यशाला आयोजित

‘बहुत सारे व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। सड़क दुर्घटना होने पर आम लोगों को संवेदनशील होकर घायल व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास करने चाहिए। घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर और अच्छा मददगार होने से उसकी जान बचाई जा सकती है।’

यह विचार ‘कट्स’ जयपुर एवं ‘ऑक्सफोर्ड शिक्षण प्रशिक्षण एवं विकास संस्थान’ कोटा के तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा विषयक कार्यशाला में कोटा ट्रैफिक के पुलिस अधिकारी राजेन्द्र सिंह कविया ने व्यक्त किए। कार्यशाला में इससे पूर्व ‘कट्स’ के उप निदेशक दीपक सक्सैना ने प्रस्तुति करण के माध्यम से नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के बारे में विस्तार से बताया साथ ही अधिनियम की धारा 134 की भी जानकारी दी।

स्थानीय एडवोकेट भुवनेश शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम 2019 के बारे में बताते हुए कहा कि नए कानून में सड़क सुरक्षा के तहत यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर अब भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही दुर्घटना में शिकार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले एक अच्छे मददगार को प्रोत्साहित किया गया है।

कार्यशाला में डॉ. कुलवंत गौड़ ने कहा कि घायल व्यक्ति को चिकित्सालय पहुंचाने और उसकी जान बचाने में सहयोग करना आम व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी राम भरोस गौतम ने बताया कि चिकित्सक सड़क दुर्घटना में घायल व्शक्ति को तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहते हैं। ‘ऑक्सफोर्ड शिक्षण प्रशिक्षण एवं विकास संस्थान’ के अनवर अहमद खान ने अच्छा मददगार के बारे में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि किसी की जान बचाना इंसानियत है।

एक अवधि के बाद वाहन होंगे कबाड़

अब सरकारी व कमर्शियल वाहन 15 साल और निजी वाहन 20 साल बाद स्क्रैप (कबाड़) में चले जाएंगे। स्क्रैप प्रमाण-पत्र के आधार पर नया वाहन खरीदने पर कंपनियां 5 फीसदी की छूट देंगी। निजी वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क पूरी तरह फ्री, रोड टैक्स में 25 फीसदी और कमर्शियल पर 15 फीसदी तक की छूट मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई व्हीकल स्क्रापेज पॉलिसी की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि नई नीति से अगले 25 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। नीति की घोषणा के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। प्रधान मंत्री ने कहा कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी। सेहत, ईंधन और रख-रखाव में भी बचत होगी। *(रा.प., 14.08.21)*

प्रदेश में जीवन रक्षक योजना प्रारंभ

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5 हजार रुपए एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित करने के लिए वित्त विभाग की ओर से प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। यह योजना जीवन रक्षक योजना के नाम से जानी जाएगी।

चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि बजट घोषणा के अनुसार योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा विभाग के माध्यम से होगा। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जल्द अस्पताल तक पहुंचाने से उसकी जान बचाई जा सकती है। सरकारी एवं निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित होंगे। योजना के लिए 5 करोड़ की राशि सड़क सुरक्षा कोष से जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को अग्रिम आवंटित की जाएगी। *(रा.प.एवंदै.भा., 17.09.21)*

घटिया हेलमेट लगाने पर लगेगा जुर्माना

सड़क दुर्घटनाओं में घटिया हेलमेट के इस्तेमाल की वजह से हो रही मौतों को रोकने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत बिना स्टैंडर्ड मानक का हेलमेट पहना तो अब एक हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा।

मानक के तहत हेलमेट नहीं होने पर निर्माता और बेचने वाले को पहली बार 2 लाख रुपए तो दूसरी बार 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 माह की सजा का प्रावधान है। घटिया हेलमेट पहनने वालों को बिना हेलमेट की श्रेणी में माना जाएगा। हेलमेट निर्माता कंपनियां सब स्टैंडर्ड के हेलमेट का निर्माण नहीं कर सकेंगी। वह वास्तविक स्टैंडर्ड के हेलमेट का ही निर्माण कर सकेंगे। *(दै.भा., 12.08.21)*

प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर सख्ती

ट्रैफिक पुलिस शहर में नो हॉकिंग जोन में हॉर्न बजाने पर सख्ती बरतेगी। स्कूल, मॉल, अस्पताल और चिन्हित जगहों पर हॉर्न बजाने वाले लोगों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश का कहना है कि तेज हॉर्न बजाने वालों पर नकेल कसने के लिए डीजीपी ने निर्देश दिए हैं। शुरुआत में समझाइश की जाएगी फिर चालान होगा।

डीसीपी श्वेता धनखड़ ने बताया कि हॉर्न बजाने से लोगों को परेशानी होती है। पहले से ही चिन्हित स्थानों को सख्ती से नो-हॉर्न जोन बनाया गया है। इसके लिए चिन्हित जगहों पर एक अधिकारी के साथ पुलिस के जवान लगाए जाएंगे। पहली बार हॉर्न बजाते पकड़े जाने पर मौके पर ही जिम्मेदार को समझाया जाएगा। इसके बाद दुबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं सुधरे तो एक हजार रुपए का चालान कटेगा। *(दै.भा., 03.09.21)*

उपभोक्ता फैसले

फ्लैट का कब्जा समय पर नहीं देना 'सेवा दोष'

राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर में अशोक कुमार दिलबागी ने सहारा सिटी होम्स के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। दर्ज मामले के अनुसार उन्होंने टोंक रोड पर एक टाउनशिप में आवासीय फ्लैट्स स्वीमिंग पूल, प्ले-ग्राउंड हैल्थकेयर सहित अन्य सुविधाओं का विज्ञापन देख कर फ्लैट बुक कराया था। उन्होंने फ्लैट की अलॉटमेंट की एवज में मांगी गई पूरी राशि भी सहारा सिटी होम्स को जमा करा दी। लेकिन सहारा सिटी होम्स ने न तो परिवादी अशोक कुमार दिलबागी को फ्लैट का कब्जा ही दिया और न ही उन्हें जमा राशि ही लौटाई।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता राज्य आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा ने समय पर परिवादी को फ्लैट का कब्जा नहीं देने को सेवा में कमी का दोषी माना। आयोग ने सहारा सिटी होम्स पर दो लाख रुपए का हर्जाना लगाया। साथ ही आयोग ने फ्लैट बुकिंग व अलॉटमेंट के नाम पर सहारा सिटी होम्स द्वारा ली गई राशि 27 लाख 43 हजार 210 रुपए मय 9 प्रतिशत ब्याज सहित तीन महीने की अवधि में अशोक कुमार दिलबागी को लौटाने के आदेश दिए हैं। *(रा.प., 07.07.21)*

बिल्डर को महंगा पड़ा समय पर फ्लैट नहीं देना

जयपुर निवासी संतोष गुप्ता, माणिक चंद गर्ग, दिनेश जैन और मंजूरानी ने जिला उपभोक्ता आयोग में आस्था बिल्डहोम के खिलाफ अलग-अलग परिवाद दर्ज कराए थे। जिसमें कहा गया था कि उन्होंने आस्था बिल्डहोम की आवासीय योजना में फ्लैट बुक कराया था। जिसके लिए बैंक से ऋण लेने के साथ आवश्यक राशि भी जमा कराई थी । इसके बाद भी आस्था बिल्डहोम द्वारा उन्हें समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया। मामले की सुनवाई पर बिल्डर की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से 18 माह में फ्लैट का कब्जा देने का कोई करार नहीं हुआ था। बजरी सप्लाई बंद होने की वजह से फ्लैट बनाने का काम बाधित हुआ है।

आयोग के अध्यक्ष भगवान दास अग्रवाल व सदस्य नीलम शर्मा ने माना कि बिल्डर के सेवा दोष के चलते परिवादियों को फ्लैट का समय पर कब्जा नहीं मिल पाया। इससे वे उसके उपयोग और उपभोग से वंचित रहे हैं। आयोग ने आस्था बिल्डहोम को सभी मामलों में चार-चार लाख रुपए हर्जाना और ग्यारह-ग्यारह हजार रुपए परिवाद व्यय के तौर पर चुकाने के आदेश दिए हैं। साथ ही जमा कराई गई राशि भी मय 12 फीसदी ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए। *(रा.प., 20.08.21)*

<u>ग्राम स्तरीय जगरुकता बैठक आयोजित</u>

उचित, स्वास्थ्य वर्धक एवं सुरक्षित भोजन के लिए किया प्रेरित

'कट्स' मानव विकास केंद्र, चित्तौड़गढ़ द्वारा 'सीआईआई-एचयूएल' के सहयोग से संचालित परियोजना के तहत चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिलों की 12 ग्राम पंचायतों में महिलाओं और बालिकाओं को उचित, स्वास्थ्यप्रद व सुरक्षित भोजन और भोजन करने की अच्छी आदतों के बारे में जागरुक किया जा रहा है।

हाल ही चित्तौड़गढ़ ब्लॉक के एराल व नेतावलगढ़ पाछली एवं भीलवाड़ा जिले की कोदू कोटा ग्राम पंचायत में आयोजित बैठकों में महिलाओं को सुरक्षित रूप से भोजन नहीं करने से होने वाली बीमारियों की जानकारी देते हुए बताया गया कि पिछले वर्ष 2020 के दौरान दो लाख 33 हजार बच्चों की मौत घातक बीमारी डायरिया के कारण हो गई। ऐसी खाद्यजनित बीमारियों से बचने के लिए हमें अच्छी आदतों जैसे खाना बनाने और खाना खाने से पहले साबुन से 20 सैकण्ड तक हाथ धोना जरूरी है। सभी को यह आदत बच्चों को भी सिखानी होगी।

अच्छा भोजन जिसमें हम 'तिरंगा थाली'(केसरिया रंग में दालें, फल आदि तथा सफेद रंग में चावल, छाछ, दही आदि और हरे रंग में हरी सब्जियां एवं फल आदि) का उपयोग कर सकते हैं। महिलाओं को रसोई या जहां खाना बनाते हैं वहां साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। खाने को ढ़ककर रखना चाहिए, ताकि मक्खी मच्छर आदि खाने को दूषित नहीं करें।

इस परियोजना का खास मकसद जिलों में चुनिंदा ग्राम पंचायतों में ग्रामीण समुदाय को एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के प्रति जागरूक करना है। साथ ही खाद्य से संबंधित खुदरा प्रतिष्ठानों में काम करने वालों, खाद्य आपूर्ति सेवा में लगे लोगों, घरों में खाना बनाने वाली महिलाओं आदि को भी इस अभियान में जोड़ा गया है ताकि सुरक्षित भोजन की आदतों को पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सके। अभियान के तहत बच्चों व पुरुषों को भी स्वच्छ भोजन के बारे में नुक्कड़ नाटक जैसी अन्य गतिविधियों के माध्यम से जागरुक किया जा रहा है।

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)